अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–214 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ रविवार 3 दिसम्बर 2023 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

लखनऊ विश्वविद्यालय मे शाम ए मौसिकी कार्यक्रम का हुआ आयोजन

लखनऊ। दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत लैंगिक संवेदनशीलता प्रकोष्ठ और अभिनव गुप्ता संकाय ऑफ एस्थेटिक्स एवं शैव दर्शनशात्र के संयुक्त तत्वाधान में शाम ए मौसिकी कार्यकम का आयोजन किया गया। जिसमें सूफी, कथक, कवाली एवं अन्य गीतों की विश्विद्यालय के छात्र एवम छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गयी। कार्यकम का प्रारंभ नंदिनी सहाय के गीत सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा की गई जिस पर अंतरा श्रीवास्तव के कथक नृत्य प्रस्तुत किया। गिटार पर अभिन्न श्याम तिवारी, सिंथेसाइजर पर शिवांश चौरसिया, ढोलक पर कुशाग्र पांडेय, बांसुरी पर नरेंद्र नाथ पाठक और ढोलक पर कृतिका कुमार ने समान बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन मरियम शौकत ने किया और इस कार्यकम की संयोजिका थीं। लैंगिक संवेदनशीलता प्रकोष्ठ की कन्वेनर प्रो रोली मिश्रा और अभिनव गुप्ता संकाय की अधिष्ठाता प्रो रश्मि कुमार कार्यकम में विभिन्न विभागों के शिक्षक गन , छात्र छात्राएं भारी संख्या में उपस्थित रहे।

मंण्डलायुक्त ने बीकेटी तहसील पहुंचकर सुनी समस्या,15 प्रकरण का निस्तारण मौके पर किया गया

लखनऊ। मंण्डलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज तहसील बीकेटी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मौके पर फरियादियों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंडलायुक्त को शिकायत कर्ता शैलेंद्र द्वारा बताया गया कि लेखपाल सुजीत, राजेश तिवारी एवं सतपाल द्वारा कार्य में शिथिलता व धन उगाही की जा रही है। जिसके संबंध में मंडलायुक्त ने संबंधित लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये साथ ही लेखपाल राजेश तिवारी के प्रकरण की जांच कराते हुए अगर दोषी पाये जाते है। तो उनके खिलाफ विभागीय कार्वाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग करने वाले भू–माफियाओं व संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। साथ ही शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है। तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाये, जिससे कि आम जनमानस को वास्तविक न्याय मिल सके। वहीं वृद्धावस्था पेंशन में लापरवाही व शिथिलता की शिकायत मिलने पर एडीओ समाज कल्याण सुहेल अहमद के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने भू–माफियाओं को लेकर कहा कि अवैध कब्जा करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जाये और जमीनों को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाये, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जाएगी। मंडलायुक्त ने मौके पर 215 शिकायत को सुनकर 15 शिकायतों का निस्तारण किया।

यूपी सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए तीन नये एसडीआरएफ का किया गठन

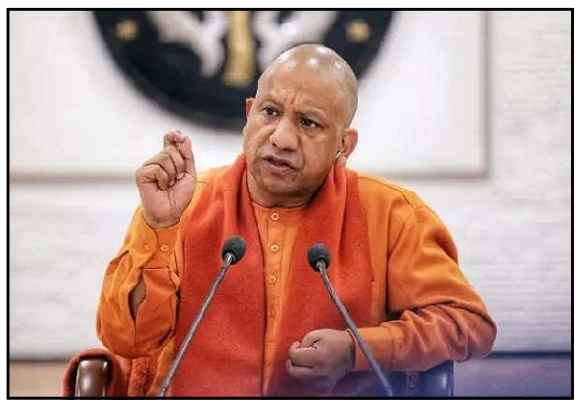

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को आपदा (बाढ़, सूखा, भूकंप, आकाशीय बिजली) के दौरान जल्द से जल्द राहत पहुंचाने एवं जनहानि को रोकने के लिए तीन नये राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का गठन किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 11 आपदाओं को राज्य आपदाओं की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें नौका दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन्यजीव द्वन्द, नदी में डूबना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदाओं से बचाव व आम लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर राहत चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। राहत आयुक्त जी.एस. नवीन ने शनिवार को एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बाढ़, अचानक आई बाढ़, मच्छर जनित बीमारियों, औद्योगिक दुर्घटनाओं, भूकंप, नाभिकीय खतरों समेत किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत बनाने के निर्देश दिये थे। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में

प्रदेश में तीन नए राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया जा रहा है। वहीं, नए बलों के लिए 80.75 करोड़ रूपये से उपकरण एवं 9.99 करोड़ रुपये से वाहन खरीदे जा रहे हैं। राहत आयुक्त ने बताया कि मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश की सभी तहसीलों में 450 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस), ब्लॉक स्तर पर 2 हजार ऑटोमैटिक रेन गेज (एआरजी) और प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में 5 'डॉप्लर रडार की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में आपदाओं से बचाव व आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर लगभग सात हजार राहत चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनों को आपदाओं से बचाव व तैयारी, आपदा के दौरान क्या करें व क्या न करें आदि के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नौका दुर्घटनाएं रोकने के लिए नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020 बनाई है जिसके जरिये प्रथम चरण में 872 गोताखोर एवं 5123 नाविकों को नाव सुरक्षा किट का वितरण किया गया है।

आनंदीबेन पटेल ने 'भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं का किया आह्वान

लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को राजभवन के बड़े लॉन में स्वयं सेवी संस्था 'उम्मीदश द्वारा भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 500 बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आयोजित 'भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए स्वयं सेवी यहां छोटे–छोटे बच्चों का उत्साह एवं आत्मविश्वास देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम खेलना भूल गए हैं। अब सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करना ही पढ़ाई का उद्देश्य रह गया है। इसलिए खेल के प्रति बच्चों में उत्साह और जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रकार के परंपरागत प्रयास करने होंगे। आज जो प्रतियोगिताएं यहां चल रही हैं। ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। कार्यक्रम में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को सड़क से हटाकर उन्हें संबल प्रदान करना, संरक्षण देना तथा

संस्थाओं का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं, कम्पनियों का आह्वान किया कि वे भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को इस पेशे से विमुक्त करने तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे आएं। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने कुलाधिपति होने के नाते विश्वविद्यालयों को भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए कहा है। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज राजभवन छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा है। मुझे खेलों का आयोजन आवश्यक हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 'खेलो इंडिया का शुभारम्भ किया। इसका लाभ हमारे बच्चों को मिल रहा है। सरकारें खेलों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे बच्चे होनहार होने के साथ–साथ सशक्त हो। उन्होंने कहा कि आज आब–ओ–हवा खराब हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपने आने वाले भविष्य के उज्जवल जीवन के लिए सार्थक शिक्षा से जोड़ना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरकार तथा समाज का दायित्व है कि वे उनके अभिभावकों को भी जागरूक करें ताकि भविष्य में वे अपने बच्चों से भिक्षावृत्ति न कराते हुए उन्हें शिक्षा से जोड़े। इस अवसर पर लखनऊ की मेयर श्रीमती सुषमा खकर्वाल, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डा. सुधीर एम. बोबडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे।

यूपी के कई जिलों में होगी बारिशय अब बढ़ेगी ठंड, आईएमडी का अलर्ट जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब दिनों दिन मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश के बाद अब ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है। जैसे–जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे–वैसे ही प्रदूषण का स्तर भी संभावना जताई है। बारिश के बाद प्रदेश में ठंड काफी बढ़ जाएगी। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत कई इलाकों की हवा लगातार खराब हो रही है। इन जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश तो

बढ़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि आने वाले दो से तीन दिनों में यूपी के कई जिलों में बारिश होगी। जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है और ठंड भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले दो से तीन दिन यूपी में बारिश होगी। विभाग ने झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, फतेहपुर उन्नाव रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी फैजाबाद, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर समेत कई इलाकों में बारिश की हुई, लेकिन प्रदूषण को कम नहीं कर पाई। जैसे–जैसे सर्दी बढ़ रही है हवा में प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आंखों में जलन और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर–116 में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 दर्ज किया गया और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। नोएडा में सुबह से ही स्मॉग देखने को मिला है। वहीं गाजियाबाद में स्थिति और भी ज्यादा खराब है. यहां लोनी में एक्यूआई 341 दर्ज किया गया और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है।

मायावती ने की जातीय जनगणना को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीपीएस) प्रमुख मायावती ने देश में जातीय जनगणना की मांग करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के लिए अब इस मुद्दे पर बिना देरी के सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया है। बसपा प्रमुख ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चार दिसंबर से शुरू हो रहे संसद बदहाल सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण–अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जातीय जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि जागरूकता है वह भाजपा की नींद उड़ाए है तथा कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में व्यस्त।

के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की गई। अब जबकि इसकी मांग देश के कोने–कोने से उठ रही है, केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलम्ब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मायावती ने कहा, वैसे विभिन्न राज्य सरकारें सामाजिक न्याय की दुहाई देकर आधे–अधूरे मन से जातीय जनगणना कराकर जनभावना को काफी हद तक साधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव है। जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जातीय जनगणना कराकर लोगों को उनका हक देना सुनिश्चित करेगी।

नामांतरण के नाम पर आवंटी से सुविधा शुल्क वसूलने के आरोप में कनिष्ठ लिपिक निलम्बित

कनिष्ठ लिपिक पर सम्पत्ति की फाइलों से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने का भी है आरोप, आवंटियों ने जनता अदालत में की थी शिकायत

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बाबू के खिलाफ की कार्यवाही, विभागीय जांच के आदेश

अवध की आवाज ब्यूरो

~~लखनऊ। लखनऊ~~ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को कनिष्ठ लिपिक अरविंद कश्यप को निलम्बित कर दिया। अरविंद कश्यप पर नामांतरण के नाम पर आवंटी से अनर्गल रूप से धन उगाही करने तथा सम्पत्ति की फाइलों से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करके आवंटियों का कार्य प्रभावित करने का आरोप है। जिसके सम्बंध में आवंटियों द्वारा जनता अदालत समेत विभिन्न फोरम में शिकायत भी की गयी थी। उपाध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाबू को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिये हैं।

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि आवंटी चेतन सक्सेना द्वारा कनिष्ठ लिपिक अरविंद कश्यप के खिलाफ शिकायत की गयी थी। चेतन सक्सेना के मुताबिक अरविंद ने जानकीपुरम योजना के सेक्टर–जी स्थित भवन संख्या एल0आई0जी0–45 का नामांतरण कराने के नाम पर उनसे ऑनलाइन म्यूटेशन फीस जमा कराने के साथ ही पूरा काम कराने के एवज में 20 हजार रूपये की मांग की थी। आरोप है कि बतौर पेशगी 10 हजार रूपये वसूलने के बाद भी अरविंद कश्यप ने उनका काम नहीं करवाया। जांच में पाया गया कि तत्समय के कार्य विभाजन के अनुसार अरविंद कश्यप द्वारा सेक्टर–जी का कार्य देखा भी नहीं जा रहा था। इसके बावजूद अरविंद कश्यप ने चेतन सक्सेना को अनर्गल रूप से उनका काम कराने का झांसा देकर धन उगाही की।

इसके अलावा अरविंद कश्यप द्वारा सम्पत्ति की फाइलों से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने की शिकायतें भी प्राधिकरण दिवसध्जनता अदालत समेत विभिन्न फोरम में प्राप्त हो रही थीं। जिससे आवंटियों का कार्य प्रभावित हो रहा था और प्राधिकरण की छवि धूमिल हो रही थी। उक्त शिकायतों पर विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी को प्रारंभिक जांच सौपीं गयी थी। इसमें प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कनिष्ठ लिपिक अरविंद कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये विभागीय जांच के आदेश दिये हैं। उक्त प्रकरण में विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें 15 दिन में विस्तृत जांच करके रिपोर्ट देनी होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज की राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की याचिका शनिवार को खारिज कर दी है। भानवी सिंह की बहन साध्वी ने भानवी और एक न्यूज चौनल से जुड़े 3 लोगों पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में साजिश, मानहानि और महिला की गरिमा हनन के आरोप में केस दर्ज कराया था। इसी केस के सिलसिले में अपने खिलाफ संभावित कार्रवाई पर स्टे लेने की गरज से भानवी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वो अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।साध्वी सिंह ने भानवी और अन्य पर आरोप लगाया है कि 28 अगस्त की शाम चौनल पर उनके जीजा राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। उसमें जीजा साली यानी श्साध्वी और रघुराज प्रताप के बीच संबंधों को लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। साध्वी सिंह की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज थाना पुलिस ने भानवी सिंह और अन्य

तीन लोगों पर केस दर्ज किया था। थाने में दर्ज तहरीर के मुताबिक, साध्वी की बहन भानवी सिंह और उनके बीच पैतृक जमीन को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में भानवी सिंह ने अपनी मां के साथ मिलकर उनके साथ कई बार मारपीट की है। कई बार पुलिस भी बुलानी पड़ी। अब भानवी उन्हें बदनाम करने की नीयत से ऐसे आरोप लगा रही हैं।साध्वी की दलील है कि उनकी दो बेटियां हैं। इस तरह के आरोप लगने के बाद वो दहशत में हैं। विवाह के कुछ वर्षों बाद से ही राजा भैया और भानवी सिंह के बीच खटास बढ़ती गई। राजा भैया ने साल 2022 में दिल्ली की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी लेकिन भानवी राजा भैया को तलाक देने को राजी नहीं थीं। साकेत कोर्ट में केस चल रहा है।

पिछले साल 1.65 लाख करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सके विभाग, घटा राजकोषीय घाटा

लखनऊ। पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट में दी गई व्यवस्था के मुकाबले विभाग 1,65,696 करोड़ 33 लाख रुपये खर्च नहीं कर पाए थे। इस वर्ष 6,85,555 करोड़ 91 लाख रुपये 92 अनुदानों के तहत खर्च के लिए रखा गया था। जिसके सापेक्ष 5,19,859 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च हो सके थे। 4.17 लाख करोड़ रुपये राजस्व मिला था । सरकार को विधानमंडल में पेश सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को विभिन्न राजस्व मदों से 4,17,241 करोड़ 50 लाख रुपये मिले थे। ये राजस्व वैट, निगम व आयकर,उत्पाद एवं सीमा शुल्क, स्टांप व पंजीयन, करेत्तर राजस्व, केंद्र सरकार से अनुदान आदि से मिले थे। सरकार की उपलब्धि रही कि 37263 करोड़ रुपये राजस्व आधिक्य था। यह राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.65 फीसदी था। राजकोषीय घाटा इस वर्ष के लिए जीएसडीपी का 3.50 फीसदी लक्ष्य के विरुद्ध 64639.26 करोड़ था जो राज्य की जीएसडीपी का 2.66 फीसदी था। इसमें राज्य सरकार ने निर्धारित मानदंडों को पूरा किया। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अन्य संस्थानों में 12479.91 करोड़ रुपये का निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक इनसंस्थानों में सरकारी निवेश 164000 करोड़ 90 लाख रुपये हो गया था। यह धनराशि राज्य की जीएसडीपी का 7.26 फीसदी था। इस वर्ष राज्य को 141.32 करोड़ रुपये का लाभांश मिला। 31 मार्च तक सरकार ने 27188.94 करोड़ रुपये का निवेश लघु व दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में की।

रिस्पांसिबल वाइल्डलाइफ टूरिज्म के लिए मिलेगा सम्मान

बीकानेर हाउस नई दिल्ली में पांच दिसंबर को होगा समारोह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से पांच दिसंबर को नई दिल्ली बीकानेर हाउस में आयोजित समारोह में रिस्पांसिबल वाइल्डलाइफ टूरिज्म में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वाले विभिन्न प्रदेशों के लोग होंगे। यूके बेस्ड एनजीओ टाफ्ट की ओर से प्रत्येक चार वर्ष में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह छठां टाफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार– 2023 है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि टाफ्ट एनजीओ व्यक्तियों, व्यवसायों, सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक उद्यमों सहित प्रकृति पर्यटन उद्योग में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पहचानने और पुरस्कृत करने का काम करता है। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सस्टीनेबल प्रैक्टिस और रिस्पांसिबल टूरिज्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। टाफ्ट पूरे भारत में असाधारण वन्यजीव पर्यटन उद्यमों और पहलों के माध्यम से दूसरों को भी इसका अनुसरण करने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करता है।पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और विशाल वन भंडार हैं। विशेष रूप से दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रामपुर में प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण–पर्यटन और इन अभ्यारण्यों के माध्यम से प्रकृति और पर्यटन के बीच सामंजस्यपूर्ण के साथ अस्तित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, रिस्पांसिबल टूरिज्म में एक सकारात्मक और शक्तिशाली मार्ग को बढ़ावा देगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में ईको पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। इस तरह के आयोजन से जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सम्पादकीय

गोल्ड बॉन्ड बंद करने की जल्दबाजी न की जाए

केंद्र सरकार ने 8 साल पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पेश किया था। उस समय से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बेचे जाने वाले इन बॉन्डों को समय–समय पर हर कुछ महीनों में बेचा जाता रहा है। अब तक ऐसी 62 किस्तें बेची जा चुकी हैं। प्रत्येक बॉन्ड की समयावधि 8 साल की है इसलिए पहली किस्त में बेचे गए बॉन्ड अपनी परिपक्वता तक पहुंच गए हैं। उन्हें वास्तविक नकदी के लिए भुनाया जा सकता है। सरकार बॉन्ड की वापसी स्वीकार करेगी और निवेशक के खाते में नकद रकम जमा करेगी। निवेशक इन बॉन्डों को पांच हजार रुपये (एक ग्राम के बराबर) या कुछ करोड़ रुपये (प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम सोने के बराबर) के रूप में खरीद सकते हैं। इन बॉन्डों के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि वे डीमैट फॉर्म में हैं इसलिए पुराने किसान विकास पत्र या ऐसे अन्य किसी बॉन्ड के विपरीत किसी भी कागज को भौतिक रूप से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे, यह बॉन्ड सोने की वास्तविक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह केवल डीमैट रूप में सोना खरीदने जैसा ही है। जिसका मतलब है कि जब आप बॉन्ड को भुनाते हैं तो यह वास्तविक सोने को भुनाने जैसा है। आपको सोने में मूल्य वृद्धि से लाभ होता है। सोने की कीमत दो कारणों से बढ़ जाती है। सोना तब महंगा होता है जब अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाज और बुलियन निवेशक एक सुरक्षित आश्रित साधन के रूप में इसे भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर देते हैं। रुपये की डॉलर विनिमय दर में गिरावट के बावजूद भारत में सोने की कीमत बढ़ सकती है। गोल्ड बॉन्ड का तीसरा फायदा यह है कि इसे लोन के लिए समानान्तर साधन के तौर पर गिरवी रखा जा सकता है। चौथा लाभ यह भी है कि बॉन्ड की अंतिम बिक्री पर किए गए पूंजीगत लाभ को करों से छूट दी गई है। पांचवां लाभ यह है कि निवेशक को न केवल मूल्य में वृद्धि का दोगुना मूल्य वृद्धि लाभ मिलता है बल्कि सरकार द्वारा निवेशक को दिया 2.5 प्रतिशत ब्याज का टॉपअप भी मिलता है। जब पहली किस्त के निवेशक अपने गोल्ड बॉन्ड को भुनाएंगे तो उन्हें 8 साल में सालाना 12 प्रतिशत से अधिक का कर लाभ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नवंबर 2015 में सोने की कीमत 2684 रुपये प्रति ग्राम थी जो अब दोगुने से ज्यादा बढ़कर करीब 6000 रुपये हो गई है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया 33 फीसदी की गिरावट के साथ 62 से 82 पर आ गया है। इस प्रकार निवेशक ने पिछले आठ वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 13.8 प्रति सैकड़ा के शेयर बाजार रिटर्न की तुलना में 8 वर्षों के लिए कर–बाद के आधार पर 12 प्रतिशत का शानदार वार्षिक लाभ कमाया है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि सोने का रिटर्न जोखिम मुक्त है और शेयर बाजार में तेजी आई है तब भी सोने ने शानदार फायदा दिया है। डीमैट गोल्ड बॉन्ड बेचकर सरकार सोने के लिए भारतीयों की अतृप्त भूख को कम करने की उम्मीद कर रही थी। हर साल भारत लगभग 1000 टन सोने का आयात करता है जिस पर औसत 50 से 80 अरब डॉलर की कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होती है। सरकार ने सोने पर 12.5 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है। यह अफसोस की बात है कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम और कड़े आयात शुल्क जैसे दो कदम उठाने के बावजूद सोने के आयात पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह सही है कि 2022–23 में सोने का आयात पिछले साल की तुलना में 24 फीसदी कम रहा और खर्च अब लगभग 40 अरब डॉलर है जो पहले की तुलना में कम है लेकिन सोने का आयात विदेशी मुद्रा पर के निकास का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यापार घाटे वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। डॉलर का निर्यात देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के शुद्ध लाभ को भी कम करता है। सरकार को उम्मीद थी कि निवेशकों को काफी आकर्षक शर्तों पर गोल्ड बॉन्ड बेचकर वह कम से कम कुछ निवेशकों को तो वास्तविक सोने से दूर कर सकेगी। गोल्ड बॉन्ड द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सोने का बकाया स्टॉक अब तक लगभग 110 टन है जो हमारे वार्षिक आयात का सिर्फ दसवां हिस्सा है। गोल्ड बॉन्ड की बिक्री के कारण सरकार द्वारा कुल उधार लगभग 64,000 करोड़ रुपये है किन्तु इस उधार की लागत प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक रही है जो उस लागत से बहुत अधिक है जो सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उधार लेने के लिए भुगतान करती है। 2008 से 2020 के बीच की अधिकांश अवधि के दौरान पश्चिमी देश अपने संप्रभु ऋण पर एक फीसदी की लागत का भुगतान करते थे जबकि भारत लगभग छह प्रतिशत की दर से भुगतान कर रहा था। अब मुद्रास्फीति और मौद्रिक सख्ती के कारण संप्रभु ऋण जुटाने की लागत बढ़ गई है फिर भी अभी स्वर्ण बॉन्ड बेचने की लागत से काफी कम है। यही वजह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने की मांग की जा रही है। यह स्कीम बहुत महंगी है और इसने भारतीयों की वास्तविक सोने के लिए अतृप्त भूख में सेंध नहीं लगाई है। लेकिन ऐसा कोई भी फैसला जल्दबाजी और समय से पहले होने वाला साबित होगा। खासकर छोटे खुदरा निवेशकों को केन्द्र में रखते हुए गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अधिक आक्रामक तरीके से बेचने की जरूरत है। गोल्ड बॉन्ड रखने की ऊपरी सीमा 4 किलो की जगह घटा कर 2 किलो की जा सकती है। बैंकों और आरबीआई के बजाय गोल्ड बांड की बिक्री को स्मार्टफोन–आधारित ऐप के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। गोल्ड बॉन्ड को स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य बनाया जा सकता है। इसके साथ ही डीमैट गोल्ड के लाभों को बहुत अधिक तीव्रता और सक्षमता के साथ विज्ञापित करने की आवश्यकता है। ऐसे विज्ञापन की कल्पना कीजिए जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे ब्रांड एंबेसडर कल्याण ज्वैलर्स के उत्पादों के साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच रहे हैं।

गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड समर्थित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साथ सह–अस्तित्व में रह सकते हैं। सरकार सोने की कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वित्तीय हानि से बचाव करके अपनी उधार लागत को कम कर सकती है। इस प्रकार यह दूसरी वस्तुओं का उपयोग करके वित्तीय हानि से बचाव करके अपनी लागत का कम से कम एक या दो प्रतिशत काट सकता है। इसके लिए नॉर्थ ब्लॉक में कुछ स्मार्ट वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता है जो पूरी तरह से संभव है। यह संभव है कि वास्तविक सोने पर गोल्ड बॉन्ड का प्रभाव गैर–रेखीय रूप से होगा। सरकार को बिना किसी दबाव का उपयोग किए या सोने के स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाए लाखों घरों में सोने को डिमटेरियलाइज करने के लिए योजनाओं को भी लागू करना चाहिए जो निश्चित रूप से भारत में अकल्पनीय है। यह स्वर्ण जमा योजना, स्वर्ण बॉन्ड योजना के साथ सह–अस्तित्व में रह सकती है और धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से औपचारिक तरल वित्तीय क्षेत्र में सोने की संपत्ति लाने में मदद कर सकती है।

मौतों वाली कार्य संस्कृति

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ताजा रिपोर्ट बतलाती है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी बहुत खराब हालात में काम करती है। स्थितियां इतनी बुरी हैं कि उनके कारण लाखों श्रमिक और कर्मचारी किसी न किसी वजह से दम तोड़ देते हैं, फिर वह चाहे काम का बोझ हो या कार्य स्थलों पर होता प्रदूषण। यह एक तरह से क्रूर पूंजीवाद के उसी चेहरे का प्रतिबिम्ब है जो मुनाफा कमाने के लिये अमानवीयता की तमाम सरहदें लांघता है। पिछले कुछ अरसे से पूंजी के मुकाबले श्रम की घटती महत्ता का भी यह साक्ष्य है।

आईएलओ की इस 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक काम से सम्बन्धित दुर्घटनाओं और विभिन्न तरह की बीमारियों के चलते विश्व में 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। यह आंकड़ा साल 2000 के मुकाबले 12 फीसदी ज्यादा तथा 2015 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है जो यह बतलाने के लिये पर्याप्त है कि लोगों का मरना बदस्तूर जारी है। जो तथ्य प्रमुखता से सामने आया वह यह है कि मौतों का सबसे बड़ा कारण है प्रति सप्ताह 55 घंटों से अधिक समय तक की काम की अवधि का होना। अकेले इसी कारण से करीब 7.5 लाख कर्मचारियों व श्रमिकों ने प्राण खोये। ऐसे में इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के उस बयान का भी स्मरण हो आता है जिन्होंने हाल ही में एक चर्चा के दौरान कहा था कि श्अगर भारत को चीन से मुकाबला करना है तो यहां के प्रत्येक युवा को सप्ताह में कम से कम 60 घंटे काम करना चाहिये। दुनिया जब 55 घंटे से अधिक अवधि तक काम करने का नतीजा बड़ी संख्या में लोगों की मौत के रूप में देख रही है, तो नारायण मूर्ति का यह बयान निष्ठुर ही कहा जा सकता है। यह पूंजीवाद का वह विद्रूप पक्ष है जिसमें कारोबारियों को लोगों की जान की परवाह नहीं होती और वे आर्थिक लाभ को ही तरजीह देते हैं। ये वे मौतें हैं जिनकी रिपोर्ट हुई है या जानकारियां दस्तावेजों तक पहुंच सकी हैं। बड़ी संख्या में ऐसे गैर–संगठित क्षेत्र के लोग हैं जो जान तो गंवाते हैं परन्तु वे घोषित आंकड़ों के हिस्से नहीं बन पाते। यह पूरी दुनिया का हाल है, लेकिन तीसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों में श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय व चिंतनीय है जो 21वीं सदी में हासिल की गई वैज्ञानिकता, तकनीकी विकास एवं आधुनिक प्रबंधन शैली के भी विपरीत है। एशियाई, अफ्रीकी एवं लातिन अमेरिका के कई अविकसित व विकासशील देशों में लोगों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। ये मौतें व्यापक पैमाने पर मानवाधिकार की दुर्दशा को भी बयान करती हैं। वर्गीकृत मौतों के अलावा सोचे–समझे बिना थोपे जाने वाले सरकारी निर्णयों के कारण भी बड़ी संख्या में कार्य स्थलों पर मौतें होती हैं। भारत में नोटबंदी एक ऐसा ही उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सनक व अदूरदर्शिता से उपजे इस फैसले का नतीजा देश ने बैंकों के बाहर लोगों की तथा बैंकों के भीतर कर्मचारियों की मौतों के रूप में देखा था। इसी प्रकार कोरोना काल में भी लोगों से लिये जा रहे काम के दौरान भी हजारों लोगों ने जानें गंवाई थीं। उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान स्थानीय निकायों के चुनाव कराये गये थे। नौकरी खोने के डर से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों ने दूर–दराज जाकर चुनावी ड्यूटी की थी। पर्याप्त ऐहतियात बरतने की सुविधा न होने और इलाज की अनुपलब्धता के कारण बड़ी तादाद में मौतें हुई थीं। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अन्य कारण तथा उनसे मरने वाले लोगों की संख्याएं इस प्रकार हैं– गैस रिसाव व आगजनी से 4.5 लाख, काम के दौरान घायल होकर 3.63 लाख, एसबेस्टस 2.09 लाख, सिलिका 42 हजार से ज्यादा, कार्य जनित अस्थमा लगभग 30 हजार, विकिरण 18 हजार, डीजल इंजिन एग्जास्ट 14700, अर्सेनिक 7600 एवं निकल से 7300। जो सेक्टर सर्वाधिक खतरनाक माने गये हैं और जिनमें सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं, उनमें खनन, विनिर्माण, बिजली तथा प्राकृतिक गैस हैं। इस रिपोर्ट पर सिडनी में चल रही 23वीं कांग्रेस में चर्चा होगी जिसमें सुरक्षित कार्य पद्धति विकसित करने सम्बन्धी उपाय सुझाए जायेंगे। काम के दौरान घायल होने वालों की संख्या तो करोड़ों में है जो यह बतलाता है कि कामकाजी जनता के लिये सुरक्षित कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब भोपाल गैस त्रासदी के करीब 40 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 व 3 दिसम्बर, 1984 की मध्य रात्रि को यहां स्थित यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से 45 टन मिथाइल आईसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इससे 15 से 20 हजार लोग मारे गये थे और करीब 6 लाख लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। इनमें बड़ी तादाद में सामान्य जनता के अलावा संयंत्र के कर्मचारी थे जो या तो कार्यरत थे अथवा आसपास ही रहते थे। बेशक मरने वाले गैर कर्मचारी अधिक हैं परन्तु यह बतलाने के लिये ये आंकड़े पर्याप्त हैं कि कर्मचारियों को किन हालात में काम करना पड़ता है। इस त्रासदी को अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा के रूप में निरूपित किया जाता है। कारखानेदारों की औद्योगिक सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण पर खर्च न करने की प्रवृत्ति से काम करने वालों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। शासकीय विभाग एवं नियामक एजेंसियां भी इस ओर ध्यान नहीं देतीं। संवेदनहीन सरकारी मशीनरी व सरकारें सर्वहारा की बजाये पूंजीपतियों की पक्षधर होती हैं जिसका परिणाम यह मौतों वाली कार्य संस्कृति है।

एग्जिट पोल की उपयोगिता?

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बारे में 'एग्जिट पोल' ने जो भविष्यवाणी की है उसकी सत्यता का पता कल रविवार को ही चल जायेगा मगर जिस प्रकार नतीजों को लेकर विभिन्न पोलों के बीच ही भिन्नता बनी हुई है उसे देख कर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि परिणाम जानने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका एग्जिट पोल करने वाली इन संस्थाओं के पास नहीं है। विज्ञान में किसी समीकरण का परिणाम अंत में एक ही आता है चाहे उसे हल करने के तरीके अलग–अलग ही क्यों न हो। हकीकत यह है कि संसदीय प्रणाली की चुनाव प्रणाली में नतीजे जानने का तरीका केवल एक ही होता है और वह होता है अनुभवी व निष्पक्ष पत्रकारों की पारखी आंख–कान व बुद्धि। मतदाताओं के नमूने लेकर उनसे सवाल–जवाब करने से उनके मन के भेद को जानना संभव नहीं होता, इसीलिए एग्जिट पोल के नतीजे अधिकतर गलत ही निकलते हैं जबकि ये अपने नतीजों में पांच प्रतिशत से भी अधिक का गलत–सही का 'मिजान' लगा कर चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जमीन की 'हकीकत को ख्वाब' बनाकर भी कभी–कभी पेश कर देते हैं।

उदाहरण के लिए अगर हम मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों को लें तो पांच एग्जिट पोल अलग–अलग परिणाम इस तरह बता रहे हैं कि एक भाजपा को 'चांद' तोड़कर दे रहा है तो दूसरा तारे उसकी गोदी में 'सितारे' डाल रहा है जबकि तीसरा उसे 'आसमान' पर बैठा रहा है और चौथा 'सान्त्वना' देता लग रहा है और पांचवां उसके 'होश' ही उड़ा रहा है और बता रहा है कि सरकार बनाने के सपने छोड़कर विपक्ष में बैठने की तैयारी करो। आखिरकार इसका क्या मतलब दर्शक और पाठक निकालेंगे? पांचों एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ध्व तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। इस मामले में सभी में एकता इस वजह लगती है कि दोनों राज्यों की जमीनी चुनावी माहौल चीख–चीख कर कांग्रेस की हवा बता रहा है। जिसका अनुमान सामान्य मतदाता भी आसानी से लगा सकता है। तेलंगाना में तो गजब का माहौल बना हुआ है जहां मुख्यमन्त्री के. चन्द्रशेखर राव के पिछले दस साल के शासन के खिलाफ बगावत जैसा वातावरण बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी यहां के कांग्रेसी मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल की जो जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले पांच सालों में चली हैं उनकी वजह से उनकी सरकार के पक्ष में ही हवा बहती नजर आ रही है। असल में भारत की चुनाव प्रणाली में एग्जिट पोल का न कोई अर्थ है और न उनकी कोई उपयोगिता है। मतदान समाप्त होने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन के बीच जो 'खाली स्थान' बना रहता है उसे भरने का काम ही एग्जिट पोलों के नतीजे करते हैं और टीवी चौनलों पर कुछ दिन के लिए शोर–शराबा और आरोप–प्रत्यारोप का दौर चलने के साथ ही 'बुद्धि विलास' भी चलता रहता है। इसलिए एग्जिट पोल का एक मात्र उद्देश्य 'समय बिताने के लिए अन्ताक्षरी' खेलने से ज्यादा नहीं लगता है। इस अन्ताक्षरी प्रतियोगिता में टीवी चौनलों में प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ कुछ स्वनामधन्य पत्रकार भी बैठकर एक–दूसरी पार्टी के खेल में पार्टियां बनकर अपने–अपने गान सुनाते रहते हैं और जनता का मनोरंजन होता रहता है। एग्जिट पोल की स्थिति यदि मनोरंजन का साधन जुटाने के सामन के रूप में हो रही है तो उनकी 'गंभीरता' का अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है। एग्जिट पोल राजस्थान के परिणामों को लेकर भी खासा मनोरंजक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पांचों पोल भाजपा को 80 से लेकर 128 सीटें तक देने का हिसाब अलग–अलग कोण से दे रहे हैं। इसका मतलब एक मानता है कि स्पष्ट बहुमत भाजपा के पास आयेगा, दूसरा मानता है कि वह अल्पमत में बैठेगी, तीसरा मानता है कि त्रिशंकु विधानसभा बनेगी और चौथा व पांचवां भी इन दोनों का औसत निकाल कर कांग्रेस व भाजपा को सीटें बांट रहा है। मगर एग्जिट पोल असली नतीजे आने से पहले अपने परिणाम देकर राजनैतिक दलों के बीच कड़वाहट को घोलने का काम भी करते हैं क्योंकि असली नतीजों में पाले बदल जाने से सत्ताधारी व विपक्षी दल के बीच कड़वाहट का भाव पैदा होने की संभावना बढ़ ही जाती है। जबकि लोकतन्त्र में राजनैतिक दल अपनी हार व जीत दोनों ही मतदाताओं का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करते हैं और जनादेश के अनुसार विधानसभा में पहुंच कर व्यवहार करते हैं। जहां तक जनादेश का सवाल है तो हमें विधानसभा चुनावों में अन्य राज्यों में जनता द्वारा दिये गये जनादेश पर निगाह डालनी चाहिए।

पिछले दिनों कर्नाटक, हिमाचल व गुजरात के चुनावों में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाओं को नकारा। इससे यह तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है इन पांच राज्यों में भी मतदाता किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देकर स्थायी सरकार बनाने का जनादेश देंगे। परन्तु असली चुनाव नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल अपने नतीजे देकर सामान्य नागरिक मतदाता को भी चुनौती देने का काम परोक्ष रूप से करते हैं इसीलिए बहुत से देशों में इन पर प्रतिबन्ध है। सबसे बड़ी बात है कि जो संस्थाएं पोल करती हैं उनकी विश्वसनीयता का पैमाना क्या है? क्या इनके पिछले एग्जिट पोल सही निकले हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि उनके निकाले गये नतीजों का मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव मतदाताओं पर नहीं पड़ेगा? क्या राजनैतिक दल अपने–अपने पक्ष में इन्हें प्रायोजित नहीं करा सकते? सवाल बहुत से उठाये जा सकते हैं।

विश्राम देने से जी उठा जंगल

उत्तराखंड की हेंवलघाटी की गोद में बसा है जड़धार गांव। यहां अस्सी के दशक तक पहाड़ों की हरियाली कम हो चुकी थी। जंगल में गिने–चुने पेड़ ही बचे थे। चारा–पत्ती, पानी और ईंधन की कमी हो गई थी। इससे चिंतित होकर गांव वालों ने पेड़ बचाने व नंगे वृक्षविहीन जंगल को हरा–भरा करने की ठानी और इसे कर दिखाया। कुछ ही सालों में जंगल जी उठा, पहाड़ों पर हरियाली लौट आई। यह बदलाव की कहानी है– उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के चम्बा विकासखंड में स्थित जड़धार गांव की। इसी इलाके में सत्तर के दशक में जंगल को बचाने का विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन हुआ था। यहां के अद्वाणी व सलेत के ग्रामीण जंगल को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि अद्वाणी व सलेत के वनों को काटने से रोकने के लिए वास्तव में पेड़ों से चिपके थे। गांधीवादी सोच का यह अनूठा सत्याग्रह था। इस आंदोलन की चर्चा देश–दुनिया में हुई थी और यहां हरे पेड़ों के कटने पर रोक लग गई थी। इस इलाके को हेंवलघाटी कहा जाता है। हेंवल नदी सिद्धपीठ सुरकंडा देवी की पहाड़ी से निकलकर आगे ऋषिकेश के समीप शिवपुरी में गंगा में विलीन हो जाती है। पहले इन पहाड़ियों में खूब बर्फ पड़ती थी, मई माह तक भी सुरकंड़ा की बर्फ नहीं पिघलती थी। एक जमाने में यह क्षेत्र बांज, बुरांस, मैरू, देवदार, रई, मुरेंडा आदि प्रजातियो के घने जंगल से ढंका रहता था। लेकिन 60 के दशक में इस कुदरती जंगल पर संकट आया। 80 के दशक तक आते–आते पूरा पहाड़ ही नंगा हो गया,जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर उस्तरा फेर दिया हो। क्षेत्र के लोगों ने जंगल काट डाले। इससे जैव विविधता का संकट तो हुआ ही यहां से निकलने वाली नदियां भी सूखने लगीं। झरने व जलस्रोत भी जवाब देने लगे। इसी इलाके में शराब विरोधी आंदोलन व चूना पत्थर के खनन के खिलाफ आंदोलन चला था, जिसकी रजत जयंती पर 28 दिसंबर (2020) को बड़ा समारोह भी कटाल्डी गांव में हुआ। इस कार्यक्रम में चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सीढ़ीदार पहाड़ पर बसे गांव के जंगल को देखने मैं कुछ साल पहले गया था। इसी गांव के निवासी हैं विजय जड़धारी, जो चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता रहे हैं। जब चिपको आंदोलन का दौर निकल गया, तो उन्होंने गांववासियों के साथ यहां के उजड़ चुके जंगल को फिर से हरा–भरा करने की पहल की। साथ ही बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया। देसी बीजों की पारम्परिक खेती को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी। उनका पारंपरिक खेती पद्धति बारहनाजा (मिश्रित खेती की पद्धति) का अनुभवजन्य ज्ञान व जानकारी उपयोगी है। उन्होंने अपने अनुभव व पारंपरिक ज्ञान के आधार पर कई किताबें लिखी हैं, जिनकी सराहना अकादमिक दुनिया में भी हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जंगल को मैंने देखा था। जंगल और पहाड़ को नजदीक से देखने का आनंद ही अलग होता है। ये हमें आज के भागमभाग और तनावपूर्ण माहौल में सदा आकर्षित करते हैं। जहां देश के अन्य इलाकों में जंगल कम हुए हैं, वहां उत्तराखंड इसका अपवाद कहा जा सकता है। विजय जड़धारी बताते हैं कि टिहरी–गढ़वाल की चंबा–मसूरी पट्टी में पहले अच्छा और सुंदर जंगल था। इस गांव में भी था। पहाड़ के ढलानों से हरियाली की चादर हटने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना रहता था। यहां के कई सदाबहार जलस्रोत सूख गए थे, तब गांववाले चिंतित हो उठे। इकठ्ठे होकर सोचने लगे, और वनों के जतन में जुट गए। जंगल बचाने की प्रेरणा चिपको आंदोलन की थी।

वे आगे बताते हैं कि जड़धार गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि जंगल को बचाया जाए। इसके लिए एक वन सुरक्षा समिति बनाई गई। जंगल से किसी भी तरह के हरे पेड़, ठूंठ, यहां तक कि कंटीली हरी झाड़ियों को काटने पर रोक लगाई गई। कोई भी व्यक्ति यदि अवैध रूप से हरी टहनी या झाड़ी काटता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा तय किया गया। कुछ समय के लिए पशु चरने पर भी रोक लगाई गई। कोई व्यक्ति वनों को किसी प्रकार नुकसान न पहुंचाए, यह सुनिश्चित किया गया। यह काम गांव की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया जिसमें जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सके। जंगल की रखवाली के लिए वन सुरक्षा समिति ने दो वनसेवक नियुक्त किए, जिन्हें गांववाले पैसे एकत्र कर कुछ आंशिक मानदेय देने लगे। जो पैसा जुर्माने से एकत्र होता उसे वनसेवकों को मानदेय के रूप में दे दिया जाता। हालांकि मानदेय की राशि कम थी, फिर भी वनसेवकों ने यह काम अपना समझकर किया। वनसेवक रहे हुकुमसिंह बताते हैं कि जंगल की रखवाली के लिए हर महीने 300 रुपए मिलते थे। 20–22 साल तक जंगल की रखवाली करते रहे। पहले 3–4 फुट छोटे पौधे थे। रूखा–सूखा जंगल था। बाद में 15 फीट ऊंचे पेड़ हो गए। जंगल में बांज, बुरांस, काफल, बमोरा, खाकसी के पेड़ बहुतायत में थे। बांज के पेड़ से चारा, पत्ती व खाद मिलती है। यह पेड़ मिट्टी को बांधने एवं जलस्रोतों की रक्षा का काम भी अन्य पेड़ों के मुकाबले ज्यादा करता है। इसका जंगल ही पानी का सदानीरा स्रोत हैं। गर्मी के मौसम में भी इसका ठंडा जल रहता है। जड़धार गांव के निवासी व स्वतंत्र पत्रकार रघुभाई जड़धारी ने बताया कि हमने जंगल को 15 साल तक कुदरती तौर पर बढ़ने दिया गया। चौकीदार रखे, जंगल को विश्राम दिया, आग से जंगल को बचाया, जहां कहीं भी धुआं देखा वहां तुरंत पहुंच जाते और आग बुझाते। इसमें गांववालों की भी मदद लेते। आग बुझाने में गांववासी बहुत मेहनत और साहस का परिचय देते हुए आग पर काबू पाते। और इस तरह जंगल में हरियाली लौट आई। पटुडी, आराकोट में भी ऐसी पहल हुई, जंगलों को बचाने का एक माहौल बन गया।विजय जड़धारी ने बताया कि हालांकि यहां वृक्षारोपण व पेड़ लगाने का काम भी प्रतीकात्मक हुआ है लेकिन वनों को फिर से हरा–भरा करने में महती भूमिका वनों को विश्राम (बंद वन) देने की है। यानी उन्हें उसी हाल में प्रकृति के हवाले छोड़ दिया जाए, जिसमें वह है। सिर्फ उनकी रखवाली की जाए और उसे पनपने दिया जाए, और बढ़ने, पल्लवित–पुष्पित होने दिया जाए। लोग जैसे अपने खेतों की देखभाल करते हैं उसी तरह जंगल की देखभाल करने लगे। धीरे–धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। दो–तीन सालों में ही सूखे जंगलों में फिर से हरियाली लौटने लगी। वे आगे बताते हैं कि शंकुधारी वृक्ष चीड़, देवदार यदि कट गए तो इनमें दुबारा कल्ले (नई कोंपलें) नहीं आते हैं। जबकि बांज, बुरांस, काफल, अथांर, घिघारू, किनगोड़, खाकसी, बमोर घने होते हैं। और उनमें 1–2 साल में ही नए कल्ले आने शुरू हो गए। झाड़ियां आ गईं। जलाऊ लकड़ियां मिलने लगीं। इससे उत्साह बढ़ने लगा।

वन सुरक्षा समिति की समय–समय पर बैठकें होती थीं। कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने मे बैठकों का दौर जारी रहा। बंद वन जागरूकता कार्यक्रम भी चलता रहा। 5–7 साल में जो जलस्रोत पूरी तरह सूख गए थे, उनमें पानी आ गया। वे कल–कल बहने लगे। इस गांव के आसपास दो दर्जन जलस्रोत हैं। नए पेड़ों ने पहाड़ को हरियाली से ढंक दिया।

बांज, बुरास, काफल के पुराने ठूंठों पर फिर नई शाखाएं फूटने लगीं। अंयार, बंमोर, किनगोड हिंसर, साकिना, धौला, सिंस्यारू, खाकसी आदि पेड़–पौधे दिखाई देने लगे। और आज ये पेड़ लहलहा रहे हैं। बारिश को समाहित करने की शक्ति पेड़ों में होती है, इससे भूक्षरण व भूस्खलन भी कम हो गया। गाय–भैंसों के नीचे बिछाने के लिए पत्ती व घास चारे व ईंधन की सुविधा हो, इसकी कोशिश की जाने लगी। 90 के दशक में यहां हरित हिमालय कार्यक्रम चला। इसे भारत सरकार व हिमालय ट्रस्ट ने संयुक्त तौर पर पायलेट प्रोजेक्ट की तरह चलाया। हमारे यहां हेंवलघाटी हरियाली कार्यक्रम के नाम से संचालित हुआ। इसके तहत् 2 साल तक वनसेवकों को मानदेय दिया गया। यह वर्ष 1991–92 की बात है। तब कश्मीर से कागजी अखरोट के बीज लाकर नर्सरी बनाई गई, अखरोट के पौधे लोगों को बांटे गए थे जो कई साल पूर्व से अब तक लोगों को अच्छी आमदनी दे रहे हैं। पिछले चार दशक से हरियाली वापसी के इस काम का नतीजा यह है कि बुरांस, काफल के सघन जंगल प्रकृति अपने आप वापस ले आई। अब जंगल इतना घना हो गया है कि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचती। जड़ी–बूटी, घास, लताएं, बेल फिर से आ गईं। काफल, बांज, बुरांस खूब हो गए। बुरांस के लाल फूल अलग ही छटा बिखेरते हैं। काफल का खट्टा–मीठा फल लोगों की पोषण सुरक्षा व रोग प्रतिरोधी शक्ति बढ़ाने का काम करता है। सूखे पानी के जलस्रोत फिर फूट पड़े, सदानीरा हो गए। यहां के कुलेगाड, मूलपाणी, लुआरका पाणी, सांतीपुर पाणी, नागुपाणी, खुलियो गउ पाणी, रांता पाणी और द्वारछिलापाणी सहित 2 दर्जन जलस्रोत हैं। ये सदाबहार जलस्रोतों से ही साल भर गांवों को पीने का पानी मिलता है। चौड़ी पत्ती के जंगल बारिश के पानी का स्पंज हैं। वे पानी को सोखकर रखते हैं। जहां ऐसे जंगल होते हैं वहां जलस्रोत सदानीरा होते हैं। पानी छन छन, कल कल बहता रहता है। इसके अलावा, कई वन्य प्राणियों ने भी इस जंगल को अपना आशियाना बना लिया है। भालू, सेही, बघेरा, तेंदुआ, बारहसिंघा, हिरण, जंगली सुअर, बंदर आदि यहां प्रायरू दिखते हैं। हिरणों की टोलियां बिचरती रहती हैं।

गोविंदबल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण व विकास संस्थानश (श्रीनगर, गढ़वाल) के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में इसे पुनर्जीवित सर्वश्रेष्ठ जंगलों में बताया है। पुणे के पक्षी विशेषज्ञ डा. प्रकाश गोले ने यहां कुछ ही घंटों में पक्षियों की 95 प्रजातियों की गिनती की। जंगल बढ़ाने में यह सहायक हुए हैं। जड़धारी कहते हैं कि दूर–दूर से यह पक्षी बीज लाकर इस जंगल के अवैतनिक सेवक बन गए हैं। ग्राम वन पंचायत यहां वन संरक्षण व वन प्रबंधन का काम करती हैं। उत्तराखंड में वन पंचायतों का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश शासन से वन पंचायतें थीं। विजय जड़धारी बताते हैं कि वन पंचायत स्वशासन का एक उदाहरण हैं। आसपास के जंगलों का रखरखाव करती हैं। यह लगभग 1927 के आसपास बनीं। जड़धार में हाल ही में 1998 में वन पंचायत बनी। जड़धार में भी वन पंचायत है, इसका जंगल में दखल बढ़ा है, पर इसे हावी नहीं होने दिया है। अब इन्हें नए सिरे से मान्यता मिली है, और सक्रिय हैं। वर्तमान में जड़धार वन पंचायत के सरपंच राजेन्द्र नेगी हैं। राजेन्द्र नेगी ने बताया कि वे वर्ष 2017 से सरपंच हैं और इस बीच उन्होंने कई काम करवाए हैं। सरकार की जायका परियोजना के अंतर्गत पौधारोपण व आजीविका सुरक्षा की है। इसके तहत् वृक्षारोपण किया गया। इसकी तार फेसिंग करवाई है, जिससे कुछ हद तक जंगली जानवर, खासकर सुअर से फसलों की सुरक्षा हुई है। स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण करवाया गया है। जल संचयन हो इसके लिए जंगल में छोटी चाल–खाल (तालाब) बनाई गई। कुल 9 चाल बनाई गई हैं। यह भी जल भंडारण का परंपरागत तरीका है। इनमें से 3 चाल में बारह महीने पानी रहता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और जलस्रोत भी सदानीरा होते हैं। जंगली जानवरों को पीने का पानी भी मिलता है। गांव के पालतू मवेशी भी पानी पीते हैं। हाल में चमोली जनपद में ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही पर विजय जड़धारी ने कहा कि यह मानव निर्मित है। इस घटना में अब तक 31 लोग मारे जा चुके हैं, और कई के लापता होने की खबर है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले केदारनाथ की घटना से कोई सबक नहीं लिया गया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट व धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदी गई। अब कंपनियां ग्लेशियर फटने को दोष दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि जलवायु बदलाव व मौसम परिवर्तन के कारण बादल फटने, ग्लेशियर टूटने, सूखा पड़ने और अतिवृष्टि होने की घटनाएं होंगी पर होनेवाली तबाही को रोका जा सकता है। हमें नदियों को बांधने की बजाय नदियों व गाड–गदेरों को खुला रखना होगा और हिमालय के साथ हो रही छेड़छाड़ को बंद करना होगा। उन्होंने इसका एक उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ साल पहले जड़धार गांव के जंगल में पहाड़ की चोटी पर बादल फटने की बड़ी घटना हुई थी पर उसका असर गांव तक नहीं पहुंचा। जंगल में ही मलवा व पानी जज्ब हो गया। इस तरह हरे–भरे जंगलों से ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होनेवाली हानि को रोका जा सकता है। कुल मिलाकर, वर्ष 1980 के बाद से गांव चारा–पत्ती, जलाऊ ईंधन व पानी के मामले में यह गांव आत्मनिर्भर है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब भी हल, जुआ, लाट जैसे खेती के औजारों के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, सब लोग जंगल मिलकर जाते हैं और लकड़ी ले आते हैं। चौड़ी पत्तियां पशुओं के नीचे बिछावन के काम भी आती हैं। गोमूत्र–गोबर आदि सड़कर जैव खाद बनाते हैं, जो बहुत उपजाऊ होती है। बांज की पत्तियां मवेशी खाते हैं, वह चारे का काम भी करती हैं। ईंधन के लिए भी अच्छी होती हैं। जलवायु बदलाव के इस दौर में जंगल को फिर से पुनर्जीवन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कुड़ी व पिपलेत गांवों में वन संरक्षण किया जा चुका है। इस पूरे काम से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांवों की आपसी समझ, एकता वनों के विश्राम और मेहनत से उजड़ रहे वनों को नया जीवनदान मिल सकता है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी, जलस्रोतों का सूखना, भूक्षरण, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। पर्यावरण का संकट बढ़ रहा है। ऐसे दौर में जड़धार के जंगल ने नया रास्ता दिखाया है। यह गांव अब पारिस्थितिकीय वापसी का भी अनुपम उदाहरण है। हाल ही के हादसे के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जड़धार जैसे जंगल ऐसे हादसों को कुछ हद तक रोकने में सक्षम हैं, जैसा कि बादल फटने से जड़धार गांव में कोई नुकसान नहीं हुआ था। कुल मिलाकर, यह सराहनीय होने के साथ अनुकरणीय भी है।

चालक महासंघ प्रतिनिधिमण्डल को एसीएस का आश्वासन

लखनऊ। राजकीय वाहन चालक महासंघ के प्रतिनिधि मण्डल ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक दैवेश चतुर्वेदी से मुलाकात कर उन्हें राजकीय चालकों की पॉच सूत्रीय मांगों से अवगत कराते हुए उनके निस्तारण की मांग रखी। अपर मुख्य सचिव ने चालक महासंघ के पदाधिकारियों की मांगों विस्तार से सुनने के उपरान्त मांगों पर सहमति जताते हुए जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में शाहिद अली प्रदेश सलाहकार राजकीय वाहन चालक महासंघ, रिजवान अहमद सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष, जयप्रकाश त्रिपाठी प्रदेश महामंत्री, वीरेंद्र पांडे प्रदेश मंत्री, रमेश कुमार प्रदेश प्रचार मंत्री सम्मिलित थे। प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अहमद ने बताया कि बैठक में अपर मुख्य सचिव के समक्ष मुख्य रूप से ग्रेड वेतन 2000 रूपये, समस्त राजकीय वाहन चालको पर लागू प्रतिशत व्यवस्था समाप्त करते हुए प्रथम नियुक्ति पर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2400, नौ वर्ष की सेवा में प्रथम प्रोन्नत वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2800, प्रोन्नति वर्ष 15 पर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 और प्रोन्नति वर्ष 18 में वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4800 रूपये दिया जाए। आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर रिक्त पदों पर भर्ती तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। ग्रीष्म कालीन वर्दी भत्ता 1500 रूपये और शीतकालीन वर्दी भत्ता 2600 तथा सिलाई मूल्य महंगाई के अनुरूप दिया जाए। जूता बाजार मूल्य 800 रूपये, कम्बल 600, छत्ता 200 रूपये, वर्दी धुलाई भत्ता 100 रूपये तथा छाते के स्थान पर प्रति दो की सेवा में रेनकोट दिया जाए। शासन एवं सरकार द्वारा जारी शासनादेश, आदेश निर्देश सभी विभागों, निदेशालय, निगमों, स्थानीय निकायों कृषि विश्वाविद्यालय, प्राविधिक,तकनीकि विश्वविद्यालयों में भी लागू किए जाए।कोई मतदाता ना छूटे– इस उद्देश्य से आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 को नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेंद्र नगर, लखनऊ की 19 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन एनसीसी विंग के कैडेट्स ने प्राचार्या प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय तथा एनसीसी अधिकारी मेजर डॉ मनमीत कौर सोढ़ी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया जिसमें विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण–2024 अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने तथा मतदान के महत्व पर बल दिया गया। महाविद्यालय में बड़ी संख्या में उन छात्राओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है जो 18 वर्ष की आयु की हो गई है अर्थात निर्वाचक नामावली में नए युवा मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रो मंजुला उपाध्याय ने कहा कि सभी नागरिकों के सामूहिक प्रयास से देश सही मायने में विकास की ओर उन्मुख हो सकता है। युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मेजर डॉ मनमीत कौर सोढ़ी ने कैडेट्स को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि प्रत्येक मत की कीमत होती है। इसलिए देश के बेहतर भविष्य के लिए सभी नागरिकों को सभी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 19उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन से नायब सूबेदार जीबी चाको भी इस अभियान में सम्मिलित रहे।कैडेट्स ने स्लोगन तथा पोस्टर के माध्यम से भी वोट के महत्व को समझाने का प्रयास किया।

आवारा कुत्तों का आतंक,एक हफ्ते में 109 लोगों को कुत्तों ने काटा, पालिका के पास कुत्तों को पकड़ने का इंतजाम नहीं

बांदा। इस समय आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। रात हो या दिन, आप जिस गली या मोहल्ले से निकलेंगे। वहां आवारा कुत्तों का झुंड मिल जाएगा। बाइक सवार या अपरिचित के गुजरते भौंकते हुए खदेड़ लेते हैं। ऐसे में कई बार बाइक सवार असंतुलित होकर

दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आवारा कुत्ते काट लेते हैं। शहरियों को इन कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, पर पालिका के पास कुत्तों को पकड़ने के इंतजाम ही नहीं हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। जहां पर करीब एक हफ्ते में 109 लोगों को कुत्ते ने काटकर जख्मी किया है। वहीं पर गांव से बाहर तक के लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। जहां कुत्तों को पकड़ने के लिए 13 टीमें लगाई गई है। आवारा कुत्तों के तलाश में जुटने के लिए 50 कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं अस्पताल में कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वहीं अभी तक एक हफ्ते में 109 लोगों को काटकर जख्मी किया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए हर वार्ड में तलाश जारी है। वहीं रोज शिकार जख्मी लोगों की अस्पताल में संख्या बढ़ती नजर आ रही है। नगर पालिका के अथक प्रयासों के बाद भी कुट्टी को पकड़ पाने में टीम के हाथ खाली हैं। वहीं घायल आमोद कुमार ने बताया की मैं सुबह शौच क्रिया के लिए जा रहा था, तभी कुत्ते ने आकर पीछे से हमला कर दिया। डॉक्टर विनीत सचान ने बताया की एक हफ्ते में 109 को कुत्तों के मामले आए हैं, जहां पर उन्हें रेबीज इंजेक्शन लगाया गया है।

अफसर हैं, मानते ही नहीं !

भू–राजस्व के वादों का निस्तारण योगी सरकार की प्राथमिकता

लखनऊ,(यूएनएस)। भू राजस्व के मामलों के निस्तारण में राजस्व विभाग और तहसील से लेकर कलेक्टरेट तक विलम्ब की शिकायत आम हो चुकी हैं। विलम्ब के कारण कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपराधिक घटनाओं का स्वरूप ले लेते हैं। का पछतावे से होत है, जब चिड़िया चुग जाए खेत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव ग्रामीण परिवेश से होने के कारण वे ऐसे मामलों की गम्भीरता से लेते हैं। उन्होंने साफ कह रखा है कि भूमि की पैमाइश हो या बंटवारा का कोई प्रकरण हो तो उसके समाधान में अकारण लटकाने की प्रवृत्ति राजस्व विभाग और पुलिस महकमे के अफसर छोड़ दें और त्वरित कार्यवाही कर समाधान करे ताकि विवाद न बढ़े। सीएम योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अफसरों को पत्र भेजकर भू–राजस्व सम्बन्धी मुकदमों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, भू राजस्व से जुड़े मुकदमों का निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। श्री गोयल ने कहा है कि आरसीसीएमएस पोर्टल की समीक्षा में संज्ञान में आया है कि कुछ राजस्व न्यायालयों में वाद को तत्काल दर्ज नहीं किया जा रहा है बल्कि दर्ज किए बिना ही मुकदमों की सुनवाई की जा रही है एवं मुकदमे में निर्णय की स्थिति आने पर ही उनको पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है। अधिक निस्तारण दिखाने के लिए कुछ राजस्व न्यायालयों द्वारा लम्बित वादों को मासान्त में एकपक्षीय खारिज कर दिया जाता है एवं उन्हीं मुकदमों को अगले माह पुनः रिस्टोर कर देते है।ऐसी कार्यवाही ठीक नहीं। भू राजस्व से सम्बंधित मुकदमों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि इस प्रकार के मुकदमों की मॉनिटरिंग राजस्व परिषद, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी स्तर से गहनता से की जाए एवं निर्धारित समयानुसार निस्तारण किया जाए। प्रक्रिया से हटकर काम किये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। राजस्व न्यायालयों में वाद दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरु से अंत तक ऑनलाइन किया जाए। शासन ने निर्देश दिए हैं कि दर्ज वादों में जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गमन की भांति हर स्तर पर समयबद्धता लागू की जाए।वाद ऑनलाइन यूनिक नम्बर जैनरेट होने पर ही दर्ज माना जाए।प्रत्येक स्तर पर हो रही कार्रवाई की सूचना एसएमएस द्वारा आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजी जाए।दर्ज वादों की स्थिति देखने की सुविधा सम्बन्धित पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।आदेशों को डिजिटल साइन से पोर्टल पर अपलोड किया जाए एवं प्रत्येक आदेश पर कीयू आर कोड अंकित हो, ताकि आदेशों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो। ई–आफिस की तरह वादों की पत्रावलियाँ पूरी तरह से ऑनलाइन होनी चाहिए।

राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी में मधुमेह दिवस कार्यक्रम आयोजित

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कालिज के राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी ने विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर 'अपडेट्स इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस' पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, केंद्र के निदेशक डॉ. हामिद अशरफ ने कहा कि भारत में दुनिया में टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिकांश रोगियों की मृत्यु 30 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। उन्होंने कहा कि टाइप 1 मधुमेह का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के लिए उत्कृष्टता केंद्र, नोवो नॉर्डिस्क एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से द्वारा समर्थित, 18 वर्ष से कम उम्र के रोगियों को मुफ्त इंसुलिन और एक इंसुलिन पेन प्रदान करा रहा है।

ने टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित महिला मदीहा ने अपनी यात्रा के बारे में एक प्रस्तुति दी, और उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस वाले रोगियों

के लिए एक प्रश्नोत्तरी (मिथक बनाम तथ्य) आयोजित की गई। इस अवसर पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई जिसमें प्रोफेसर जमाल अहमद, पूर्व डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, डॉ. आसिम सिद्दीकी, सलाहकार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, डॉ. सैयद मोहम्मद रजी, सलाहकार एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, श्री साई अस्पताल, मोरादाबाद और डॉ. अरशद बारी, सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग ने भाग लिया। प्रोफेसर जमाल अहमद ने विभिन्न प्रकार के मधुमेह मेलिटस, टाइप 1 मधुमेह मेलिटस वाले रोगियों में आजीवन इंसुलिन की आवश्यकता, इंसुलिन के प्रकार और हाइपोग्लाइसीमिया के प्रबंधन पर चर्चा की। डॉ. आसिम सिद्दीकी ने मधुमेह मेलेटस के लक्षणों और इंसुलिन वितरण उपकरणों, टाइप 1 मधुमेह मेलेटस के प्रबंधन में नवीनतम तकनीकी प्रगति और मधुमेह की दीर्घकालिक जटिलताओं पर चर्चा की। डॉ. सैयद मोहम्मद रजी ने टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के जोखिम कारकों, रक्त ग्लूकोज की निगरानी कैसे करें, उपचार के लक्ष्य, टाइप 1 डायबिटीज वाले रोगियों में आहार और टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस वाले रोगियों में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. अरशद बारी ने बढ़े हुए रक्त ग्लूकोज के प्रबंधन में व्यायाम की भूमिका, टाइप 1 मधुमेह के रोगियों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के प्रकार, टाइप 1 मधुमेह वाले बच्चों पर स्क्रीन टाइम का प्रभाव, विभिन्न प्रकार के व्यायाम और व्यायाम के दौरान सावधानियों पर चर्चा की। एएमयू के बाल रोग विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. आयशा अहमद ने पैनल चर्चा का संचालन किया।

कार्यक्रम में टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित 100 से अधिक रोगियों ने अपने माता–पिता के साथ भाग लिया। निदेशक डा. हामिद अशरफ ने मरीजों को उत्कृष्ट देखभाल प्रदान करने के लिए प्रो. एस.एस. सिद्दीकी और डॉ. अहमद आलम और श्री सैयद फखरुल हेजाज आजमी और युसरा जाकिर (मधुमेह शिक्षक) सहित अपने सहयोगियों और स्टाफ सदस्यों को रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।

राजभवन में उम्मीद संस्था द्वारा खेल महोत्सव का हुआ आयोजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन के बड़े लॉन में स्वयं सेवी संस्था उम्मीद द्वारा भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 500 बच्चों के प्रोत्साहन हेतु 'शिक्षा से शिक्षा की ओर' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित दो दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारम्भ गुब्बारे उड़ाकर किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि राजभवन छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा है। मुझे यहां छोटे–छोटे बच्चों का उत्साह एवं आत्मविश्वास देखने को मिला। जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम खेलना भूल गये हैं। अब सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करना ही पढ़ाई का उद्देश्य रह गया है। इसलिए खेल के प्रति बच्चों में उत्साह व जागरूकता पैदा करने के लिए इस प्रकार के परंपरागत खेलों का आयोजन आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि आब–ओ–हवा खराब हो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपने आने वाले भविष्य के उज्जवल जीवन के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। राज्यपाल ने समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं, कम्पनियों का आह्वान किया कि वे भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को इस पेशे से विमुक्त करने तथा उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आगे आएं। साथ ही राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए कहा है। कार्यक्रम में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को सड़क से हटाकर उन्हें संबल प्रदान करना, संरक्षण देना तथा शिक्षा से जोड़ना हम सभी का कर्तव्य है। सरकार के साथ समाज का दायित्व है कि वे उनके अभिभावकों को भी जागरूक करें। ताकि भविष्य में वे अपने बच्चों से भिक्षावृत्ति न कराते हुए उन्हें शिक्षा से जोड़े। इस अवसर स्वयं सेवी संस्था उम्मीद के संस्थापक सचिव बलवीर मान सिंह ने बताया कि यह खेल प्रतियोगिता भिक्षावृत्ति से मुक्त कराये गये मात्र 60 बच्चों से शुरू की गयी थी। जो आज लगभग 500 बच्चों तक पहुंच गयी है। आज की इस प्रतियोगिता में 3.5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चे विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल महोत्सव में जिन खेलों को शामिल किया गया है। उसमें 3.5 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिये बोरा रेस, गुब्बारा रेस, बास्केट बॉल फेंकना, एक स्थान पर खड़े होकर लंबी कूद, 60 मीटर की दौड़, चम्मच रेस, स्माइली गेंद फेंकना, जोड़े में बास्केट बॉल के साथ दौड़ना, गुब्बारे इकट्ठा कर टब में रखना, रिले दौड़ जैसे खेल शामिल हैं। जबकि 9 वर्ष से 16 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए 100 मीटर की दौड, कबड्डी, रस्सा कस्सी, 20 मीटर मेढक कूद तथा एक स्थान पर खड़े होकर लंबी कूद जैसे खेल शामिल किये गये हैं। इस अवसर पर लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डा सुधीर एम बोबडे, सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अवनीश कुमार अवस्थी, स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे।

आपदा से निपटने खातिर तीन नई एसडीआरएफ का गठन

योगी सरकार आपदा को लेकर गम्भीर, लिया बड़ा फैसला

नौका दुर्घटनाएं रोकने के लिए बनाई नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आपदा बाढ़, सूखा, भूकंप, आकाशीय बिजली के दौरान जल्द से जल्द राहत पहुंचाने एवं जनहानि को रोकने के लिए पिछले साढ़े छह वर्ष में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में तीन नई राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन किया गया, जबकि प्रदेश की 11 आपदाओं को राज्य आपदा में शामिल किया गया। नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन्य जीव द्वन्द, नदी में डूबना समेत 11 आपदाएं शामिल हैं। प्रदेश में आपदाओं से बचाव व आम जनमानस को जागरुक करने के लिए ग्राम स्तर पर राहत चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि सीएम ने प्रदेशवासियों को बाढ़, फ्लैश फ्लड, वेक्टर जनित बीमारियों, औद्योगिक दुर्घटनाओं, भूकंप, नाभिकीय खतरा समेत किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में प्रदेश में तीन नई राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया जा रहा है। नई कंपनी के लिए 80.75 करोड़ से इक्विपमेंट एवं 9.99 करोड़ से वाहन खरीदे जा रहे हैं। योगी सरकार ने अधिक से अधिक आपदा पीड़ितों को राहत फंड का लाभ दिलाने के लिए कई दुर्घटनाओं को राज्य आपदा में शामिल किया है। इसमें नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैसरिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव वन्य जीव द्वन्द, डूबना, सांड एवं नीलगाय के आघात से होने वालीमृत्यु शामिल है। स्कूलों के पाठ्यक्रमों एवं उत्तर प्रदेश के शिक्षा परिषदों में आपदा प्रबंधन के विषयों को शामिल किया गया। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस अकादमी, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सहित अन्य संस्थानों में आपदा प्रबंधन विषय शामिल है। मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश की सभी तहसीलों में 450 आटोमेटिक वेदर स्टेशन एडब्ल्यूएस, ब्लॉक स्तर पर 2 हजार आटोमेटिक रेनगेज एआरजी और प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में 5 डॉप्लर रडार की स्थापना की जा रही है। आपदाओं से बचाव व आम जनमानस को जागरूक करने के उद्घ्देश से ग्राम स्तर पर लगभग सात हजार राहत चौपालों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणजनों को आपदाओं से बचाव व तैयारी, आपदा के दौरान क्या करें व क्या न करें आदि के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।योगी सरकार ने प्रदेश में नौका दुर्घटनाएं रोकने के लिए नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति–2020 बनाई। इसके जरिये प्रथम फेज में 872 गोताखोर एवं 5123 नाविकों को नाव सुरक्षा किट का वितरण किया गया। आपदा के दौरान राहत वितरण प्रणाली को समयबद्ध व पारदर्शी बनाने के लिए इंड टू इंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ बेनिफिशरी मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इससे लाभार्थी के चयन से लेकर डिजिटल अप्रूवल तथा अकाउंट में धनराशि हस्तातंरित करने तक की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है, जिससे राहत वितरण में पारदर्शिता के साथ–साथ समयबद्धता भी सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा प्रदेश में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर में मुख्यमंत्री बाल तरणवीर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

एलडीए अर्जित भूमि का कराया जाएगा सर्वे, अभियान चलाकर हटाये जाएंगे अवैध कब्जे

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी सभी योजनाओं में अर्जित व नियोजित भूमि का सर्वे कराएगा। इनमें जिन सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण पाया जाएगा। उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने इस बाबत आदेश जारी किये हैं। इस काम के लिए उन्होंने प्रभारी अधिकारी–अर्जन, सम्बंधित जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता व मुख्य नगर नियोजक की सदस्यता में टीम भी गठित कर दी है। उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि उनके द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि कई जगहों पर प्राधिकरण की अर्जित व नियोजित भूमि पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके स्थायी व अस्थायी निर्माण करा लिये गये हैं। अभियान चलाकर सभी योजनाओं में अर्जित व नियोजित भूमि का सर्वे करेगी तथा जिन जगहों पर अवैध अतिक्रमण व कब्जे हैं। वहां अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी। उन्होंने बताया कि इस टीम में प्रभारी अधिकारी–अर्जन अरविंद त्रिपाठी के नेतृत्व में सम्बंधित योजना के अमीन, सम्बंधित जोनल अधिकारी व अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में सहायक अभियंता व अवर अभियंता तथा मुख्य नगर नियोजक केके गौतम को शामिल किया है।

'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ में सी एफ ए (CFA) इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन कार्यक्रम शुरू हुआ'

लखनऊ,(यूएनएस)। इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के वैश्विक संगठन सी एफ ए (CFA) इंस्टीट्यूट, ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ को CFA इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम (यू ए पी/ CFA) में शामिल करने की घोषणा की है। यह गठबंधन कुशल प्रबंधकों और नेतृत्वकर्ताओं का विकास करने के आईआईएम लखनऊ के उद्देश्य के अनुरूप किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट उद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों कोCFA पदनाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो कि दुनिया में सबसे सम्मानित और मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र है। भारत में CFA प्रोग्राम की बढ़ती माँग के साथ, CFA इंस्टीट्यूट ने भी लखनऊ के साथ ही भारत के 23 शहरों में परीक्षा केंद्र खोलकर देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम के लिए संस्थान या यूनिवर्सिटी को अपने पाठ्यक्रम में कम से कम 70 प्रतिशत CFA प्रोग्राम कैंडिडेट बॉडी ऑफ नॉलेज (सीबॉक) को शामिल करना होता है। इस एफिलिएशन के बाद आईआईएम लखनऊ को CFA इंस्टीट्यूट के साथ काम करने की सुविधा मिलेगी, ताकि कक्षाओं में व्यावहारिक ज्ञान दिया किया जा सके। इससे विद्यार्थियों को तो लाभ मिलेगा ही, और साथ ही वे विभिन्न सत्रों में उद्योग के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट उद्योग के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, उन्हें सीखने के लिए अन्य अद्वितीय अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा, चुनिंदा विद्यार्थियों को CFA परीक्षा के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क में भी छूट मिल सकेगी।'डीन, फैकल्टी आईआईएम लखनऊ प्रो. अजय गर्ग ने कहा,' CFA इंस्टीट्यूट यू ए पी (CFA) छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करते हुए, फाइनेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मामले में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है। यह आपसी सहयोग हर गुणों से संपन्न छात्रों को तैयार करता है, जो छात्रों को बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के साथ–साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ बनाने में सहयोग करता है।'कंट्री हेड, इंडिया सी एफ ए (CFA) इंस्टीट्यूट आरती पोरवाल ने कहा,' हमें CFA इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एफिलिएशन प्रोग्राम के साथ आईआईएम लखनऊ का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, और हम इस पार्टनरशिप के तहत होने वाले सहयोग को लेकर उत्साहित हैं। हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री और देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक टैलेंट पूल को एकसाथ मिलकर तैयार करने के लिए तत्पर हैं।

CFA इंस्टीट्यूट के हाल ही में हुए ग्लोबल ग्रेजुएट आउटलुक सर्वे के अनुसार, भारतीय ग्रेजुएट्स के बीच नई आकांक्षाएं देखने को मिली हैं, जो आर्थिक आशावाद को दर्शाता है, जिनमें से लगभग आधे लोग अपने करियर की संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के साथ–साथ करियर में उन्नति के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपस्किलिंग की अनिवार्य भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इसलिए आईआईएम लखनऊ जैसे प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, CFA इंस्टिट्यूट जैसे प्रोफेशनल समूहों और इंडस्ट्री को एक साथ आने व उन्हें अपने प्रोफेशनल स्किल्स को तेजी से बढ़ाने तथा भविष्य के लिए तैयार होने के अवसर प्रदान करने की सख्त आवश्यकता है।'डीन, प्रोग्राम्स आईआईएम लखनऊ, प्रो. विकास श्रीवास्तव ने कहा,' यह साझेदारी हमारे प्रमुख एमबीए प्रोग्राम को और अधिक समृद्ध बनाती है, जो छात्रों को शुरुआती फाइनेंसियल स्किल्स और सीखने के अलग–अलग अवसरों के साथ अधिक सशक्त बनाने का काम करती है। CFA इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर, यह छात्रों को गतिशील और प्रासंगिक शिक्षा सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक नॉलेज, स्किल्स और इंडस्ट्री लीडरशिप क्षमताओं को प्राप्त करने के साधनों से लैस करती है।

गौशाला में भूख-प्यास से दम तोड रहे गोवंश,गौवंशों को नोंच कर खा रहे कुत्ते, सभी जिम्मेदार एक दूसरे पर उठा रहे उंगली

बांदा। ऊत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गोवांशो की दुर्दसा की रुला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गोवशों की सेवा के लिए 8 कर्मचारी रखे हैं। पानी के लिए अलग से बोर कराया गया है इसके बावजूद जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते गोवशों की तड़पकर मौत हो रही है। जिंदा गौवंश को कुत्ते नोंच कर खा रहे हैं। वहीं जब स्थानीय जिम्मेदारों से सवाल किया तो वो सब एक दूसरे पर लापरवाही का टिकरा फोड़ रहे हैं। यूं तो अगर पूरे जनपद में भ्रमण करके देखने निकलेंगे तो अधिकतर जगह ऐसी दुर्दशा की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी लेकिन ये रुला देने वाली तस्वीरें विकासखंड कमासिन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पन्नाह गौशाला से सामने आई हैं। जहां जिम्मेदारों ने लापर की सारी हदें पार कर दी हैं इस गौशाला में लगभग ढाई सौ गोवंश हैं जिनकी देखभाल के लिए आठ कर्मी लगाए गए हैं। इसके बावजूद भूख प्यास से बीमार होकर गोवंश तड़प कर जान दे रहीं हैं वहीं कुत्ते नोचकर खाते नजर आए हैं जो हुक्मरानों की कार्य शैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सरकारी बजट के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा इकट्ठा किए गए लाखों के बजट पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के जिलामंत्री ने मौके में जाकर जब ऐसी वीभत्स तस्वीरें देखीं तो उनकी आंखों में आसूं आ गए। उन्होंने कहा यहां की तस्वीरें रुला देने वाली हैं। कुत्ते चील कौवा गोवंश को नोचकर खा रहे हैं खाने पीने को कोई व्यवस्था नहीं हैं वहीं उन्होंने मृत गोवंश का खुद अंतिम संस्कार कर गोवंशों को दफन किया गया। इसी मामले में जब सचिव से बात की गई तो उन्होंने दुर्दशा का पूरा ठीकरा प्रधान पर फोड़ दिया कहा कि प्रधान दबंगई दिखाता है उनकी कोई बात नही सुनता वहां एक भी कर्मचारी दौरा करने पर नहीं मिलता कई बार प्रधान उन्हें खुद गौशाला में प्रवेश नहीं करने देता इसकी शिकायत कई बार अधकारियों से की साथ ही जिलाधिकारी की मीटिंग में भी यह विषय रखा गया पर हालत जस के यस हैं।

एनटीपीसी दादरी प्रबंधन ने गिनाया एक वर्ष की उपलब्धियां,120 छात्राओं को दिया गया है प्रशिक्षण

नोएडा। एनटीपीसी दादरी में आयोजित मीडिया के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्य महाप्रबंधक (दादरी) गंपा ब्रह्माजी राव ने वर्ष 2022–23 के दौरान विद्युत स्टेशन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के विषय में चर्चा की। दादरी परियोजना की पहचान विशिष्ट परियोजनाओं के रुप में की जाती है। क्योंकि परियोजना के अंदर एक साथ ताप विद्युत स्टेशन, गैस परियोजना, सोलर पावर प्लांट फ्लू गैस डीसल्फराईजेशन (एफजीडी), ड्राई सॉरबेंट इंजेक्शन सिस्टम (डीएसआई), शुष्क राख निस्तारण प्रणाली एवं एचबीडीसी के साथ सबसे अधिक क्षमता का 400 केवी और 220 केवी स्विचयार्ड स्थापित है। कार्यक्रम के दौरान बी राव ने कहा कि मीडिया 20वीं सदी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। जो आसपास घट रही सटीक जानकारी विभिन्न माध्यमों से जन–जन को अवगत कराता है। समीपवर्ती क्षेत्र के विकास हेतु सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत परियोजना प्रभावित 25 ग्रामों में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, आरओ द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा सोलर स्ट्रीट लाइटें व हाई मास्ट टावर स्थापित किये गये है। परियोजना प्रभावित 18 गांवों में स्वास्थ्य शिविर तथा फॉगिंग स्प्रै, टाउनशिप स्थित अस्पताल में एनआईओएच के साथ हुए अनुबंध अनुसार एनएफडीआरसी की स्थापना कर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग एवं ट्राई साईकिल, बैसाखी व हियरिंग उपकरण, टीबी जैसी बिमारी की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ सहभागिता बतौर डाट सेंटर का संचालन किया जाता है। बी राव ने अपने संबोधन में समीपवर्ती ग्रामों की प्रतिवर्ष सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 5 उत्तीर्ण 120 छात्राओं को बालिका सशक्तिकरण के अंतर्गत एक माह का प्रशिक्षण देकर कक्षा छः हेतु प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही टॉप टेन छात्राओं को अपने टाउनशिप स्थित डीपीएस स्कूल में प्रवेश दिलाकर निशुल्क शिक्षा दिलाई जा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधक (मानव संसाधन) विल्सन अब्राहम ने एनटीपीसी दादरी सीएसआर द्वारा समीपस्थ क्षेत्र के विकास हेतु संचालित गतिविधियों की जानकारी के साथ ही प्रतिनिधियों का आभार प्रकट करते हुए अवगत कराया। एनटीपीसी क्षेत्र के विकास के प्रति सजग एवं संकल्पित हैं। कार्यक्रम में महाप्रबंधक (ओएंडएम) जीयुवीएम राव, महाप्रबंधक (प्रचालन) राजशेखर पाला, महाप्रबंधक (अनुरक्षण एवं ईधन प्रबंधन) एनएन सिन्हा, एनटीपीसी अस्पताल के सीएमओ, कमल प्रकाश पुरुषोत्तम, अपर महाप्रबंधक (पीएंडएस) वीके गर्ग, अपर महाप्रबंधक (ईएमजी) वाणीश कुमार झा सहित अन्य विभागाध्यक्ष एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रबेका जरारड़, कार्यपालक (नैगम संचार) ने किया।

विश्व एड्स दिवस पर एएमयू में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

अलीगढ़। विश्व एड्स दिवस पर वैश्विक पहल के अनुरूप, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग तीसरे सेमेस्टर के छात्रों ने एएमयू के जेएन मेडिकल कालिज के ट्रॉमा सेंटर ओपीडी में 'नुक्कड़ नाटक' का प्रदर्शन किया।

कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो फरहा आजमी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य एचआईवीध्एड्स, इसके कारणों और एलिसा परीक्षण जैसे नैदानिक मूल्यांकन के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। पैरामेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम एक समारोह के साथ शुरू हुआ, जिसमें छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉ. वासिल हसन, डॉ.अनुराधा सिंह, साइमा अहसन एवं आतिका खान उपस्थित रहीं। सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा विश्व एड्स दिवस की शपथ ली गई। कार्यक्रम का संचालन सुश्री इंशा फिरोज ने किया।

एएमयू के कृषि विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर अकरम अहमद खान द्वारा एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, समन्वयक, बी. एससी. कृषि, शिक्षकों, गैर–शिक्षण कर्मचारियों और संकाय के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों ने समारोह में सक्रिय रूप से उत्साहपूर्वक भाग लिया। एएमयू के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन संकाय ने विश्व एड्स दिवस मनाया, जिसमें मेडिसिन संकाय की डीन प्रोफेसर वीना माहेश्वरी ने स्टाफ

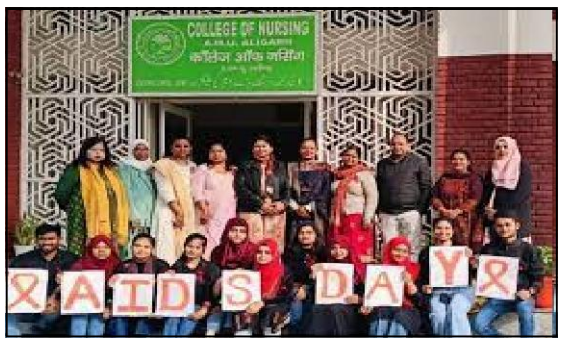

सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग ने विभाग के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एड्स संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया और एचआईवी पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और एक व्याख्यान का आयोजन किया।विभाग की अध्यक्ष प्रो. जेहरा मोहसिन ने शिक्षकों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई।एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्राचार्य डा. मोहम्द आलमगीर ने एड्स की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए शपथ दिलाई। श्रीमती तहमीना अशरफ ने बताया कि हम एड्स को कैसे रोक सकते हैं, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हम इस सिंड्रोम से कितनी सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। विद्यार्थियों ने एड्स पर आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित किये।एएमयू में बेगम सुल्तान जहां हॉल ने कर्मचारियों के लिए प्रतिज्ञा समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्हें एचआईवीध्एड्स के बारे में जागरूक किया गया। सीनियर हॉल, इंशा सिद्दीकी के नेतृत्व में, इस कार्यक्रम में एचआईवीध्एड्स के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता के महत्व पर जोर दिया गया।

एसटीएस स्कूल में अलंकरण समारोह आयोजित

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैयदना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल (मिंटो सर्कल), ने अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए आज असेंबली ग्राउंड में अपना वार्षिक अलंकरण समारोह आयोजित किया। समारोह में स्कूल और उसके सदनों के नवनियुक्त पद धारकों को विभिन्न जिम्मेदारियों से अलंकृत किया गया।

मुख्य अतिथि श्री पीरजादा ने पद धारकों को शपथ दिलाई जिन्होंने स्कूल के नियमों का पालन करने का प्रण लिया प्रिंसिपल, हेड बॉय और डिप्टी हेड बॉय के साथ, 'स्कूल ध्वज' प्राप्त किया, जबकि हाउस प्रभारियों, हाउस मास्टर्स और पोस्ट धारकों को उनके संबंधित हाउस के झंडे, बैज और सैश से सम्मानित किया गया। एस.टी. एस. स्कूल के प्रधानाचार्य फैसल नफीस ने मुख्य अतिथि एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी श्री उमर एस पीरजादा का स्वागत किया। अपने उद्घाटन भाषण में, श्री नफीस ने स्कूल की हाउस सिस्टम की दीर्घकालिक विरासत पर जोर दिया और नव नियुक्त पद धारकों को बधाई दी। उन्होंने उनसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ स्कूल के मूल्यों और परंपराओं को कायम रखते हुए रोल मॉडल बनने का आग्रह किया। श्री पीरजादा ने सर सैयद के आदर्शों पर चलने का आह्वान करते हुए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, बड़े दिल वाली सहिष्णुता और सीखने की जिज्ञासा के महत्व को रेखांकित किया।

सांस्कृतिक समन्वयक नसरीन फातिमा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री मोहम्मद तारिक (उप–प्रिंसिपल), श्रीमती समीना यूसुफ खान (प्रभारी प्राथमिक अनुभाग), और डॉ. तनवीर हुसैन खान द्वारा मंच साझा किया गया था। कार्यक्रम के संचालन में मोहम्मद अदनान खान, फरहान हबीब, मोहम्मद आसिम, मुदस्सिर अली रिजवी और डॉ. जीशान हैदर की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती आलेमा हसीन ने किया।

जेएन मेडिकल कालिज में हृदय रोग पर कार्यशाला आयोजित

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कालिज के कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा कैथ लैब में कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें नारायण हृदयालय, गुरुग्राम के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर संजय चुघ ने दायें व बांए हाथ की कलाई की धमनियों से एन्जियोप्लास्टी और एन्योग्राफी किये जाने पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हृदरोग के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं और अब जांघ की धमनियों के अलावा दोनों हाथों की कलाई की धमनियों के द्वारा एन्जियोग्राफी व एन्जियोप्लास्टी को सफलतापूर्वक अंजाम किया जा रहा है। इससे जहां रोगी को भी फायदा हो रहा है वहीं समय की बचत भी हो रही है और रेडियेशन का खतरा भी कम हो रहा है।

अध्यक्ष प्रोफेसर आसिफ हसन ने रेडियल इंटरवेंशन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उक्त प्रक्रिया के चलते बेहतर नैदानिक परिणामों, कम रक्त हानि और रोगी को कमअस्पताल में रहना होता है। प्रोफेसर आसिफ ने इसे डीएम छात्रों के लिए एक मूल्यवान शैक्षणिक अभ्यास मानते हुए अधिक कैथ लैब कार्यशालाएं आयोजित करने की घोषणा की।

कार्यक्रम में प्रोफेसर मलिक अजहरुद्दीन, डॉ. मुआज किदवई और डॉ. शाद अकबरी भी उपस्थित थे। कार्यशाला में एंजियोप्लास्टी सहित 12 मामलों का सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, सदन में भी जनता की बात नहीं सुनना चाहती है योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जनहित के तमाम मोर्चों पर विफल योगी सरकार विधानसभा में भी जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है और विधानसभा की नियमावली का उल्लघंन कर सदन की कार्यवाही मात्र तीन दिन में निपटाने की औपचारिकता निभा रही है। राय ने पार्टी के प्रदेश दफ्तर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। और दुर्भाग्य यह है कि यह अब सदन चलाकर उस पर बात भी नहीं करना चाहती। तीन दिन सदन चलाकर जनता की समस्त समस्याओं को विपक्ष के माध्यम से सदन तक नहीं आने देना चाहते। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नीति आयोग की स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है। यानि इनकी अपनी एजेन्सियां मानती हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। स्वास्थ्य विभाग की दुर्दशा का आलम यह है कि आठ नवम्बर को औरैया में अपनी बहन का शव एक भाई को मोटरसाइकिल से ले जाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का आलम यह है कि इनके अपने सांसद मुकेश राजपूत ने फरूर्खाबाद में खराब स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए। उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में 5000 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। उन्होने कहा कि गन्ना पेराई का नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पिछला भुगतान भी किसानों को पूरा नहीं मिल पाया है, जबकि नियमतरू गन्ना मिल में जाने के 14 दिनों के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिए। राय ने कहा कि गन्ना क्रय एवं ज्ञान क्रय केन्द्र पूरी तरह से भ्रष्टाचार और अराजकता का शिकार हो चुके है। पूरे प्रदेश में डी.ए.पी. और यूरिया की भारी किल्लत है, जिसके चलते खाद की कालाबाजारी चरम पर है। किसानों को लाइनों में लगकर खाद लेनी पड़ रही है जिस पर भी उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर चिन्ता जाहिर करते हुये उन्होने कहा कि एनसीआरबी के हाल में आये आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराध दर भारत के राज्यों में सबसे अधिक है। पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15.4 प्रतिशत अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। पूरे भारत में साइबर क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर है। अभी पिछले हप्ते उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने निर्देश जारी करते हुए स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में कानून व्यवस्था चिन्ताजनक है। एनसीआरबी के ही आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है। कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र चौधरी ने

कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में जाति जनगणना के सवाल पर झूठ बोलकर पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। जबकि सच्चाई यह है कि बिहार सरकार के खिलाफ केन्द्र सरकार की गुहार को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया था कि राज्य सरकार जाति गणना करा सकती है। चौधरी ने यह भी कहा कि सदन में योगी आदित्यनाथ की पिछड़ा विरोधी सरकार बेनकाब हो गयी। प्रदेश के पिछड़े समाज से योगी आदित्यनाथ और सदन में गलत तथ्य रखने वाले मंत्री सूर्य प्रताप शाही को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों का दावा करने वाली योगी सरकार में 69 हजार शिक्षक भर्ती के नौजवान पिछले 535 दिनों से धरने पर बैठें हैं और सरकार ने उनके दमन का कोई भी तरीका छोड़ा नहीं है। चौधरी ने कहा कि यूपी विधानमंडल में लागू हुए नए नियमों के अनुसार सदन दस दिन से कम नहीं चल सकता और योगी सरकार ने खुद ही यह नियम चार दिन सदन चलाकर तोड़ दिया। इससे यह जाहिर होता है कि यह लोग नियमों को लेकर कितने गंभीर हैं।

व्यापारी पुत्र अपहरण कांड,कोर्ट ने दो दिसंबर को पेश होने की दी थी अंतिम मोहलत

बस्ती। जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने व्यापारी पुत्र अपहरण कांड में फारार चल रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पुलिस अधीक्षक बस्ती को दिया है, इसके साथ नई टीम गठित कर वांछित चल रहे अमरमणि को गिरफ्तार करने को कहा है। अदालत ने दो दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए अंतिम मोहलत दिया था, लेकिन वे पेशन नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ धारा 83 की कार्रवाई की गई है। एमपी–एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने अमरमणि को पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। दो दिसंबर को सुनवाई के दौरान अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के विरूद्ध एनबीडब्लू व धारा 82 की कार्यवाही प्रचलित है, किंतु अभी तक पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी, इसलिए अमरमणि त्रिपाठी के विरूद्ध धारा 83 की कार्रवाई प्रचलित की जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में गठित विशेष टीम अपने कार्य में असफल रही, इसलिए पुलिस अधीक्षक को पुनः निर्देशित किया जाता है कि एक नयी स्पेशल टीम गठित करके अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी की समस्त चल–अचल संपत्ति का पता लगाकर उसकी कुर्की कुलिंदा अग्रिम नियत तिथि तक न्यायालय में पेश करें। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विनय पाठक के खिलाफ कर्तव्य के प्रति उदासीनता, दुराचरण, उपेक्षा के लिए पूर्व तिथि पर फौजदारी दंडात्मक वाद संख्या संस्थित किया गया था, बताया कि उन्होने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि मीडिया सेल द्वारा कंप्यूटर पर कट पेस्ट के द्वारा त्रुटि वश व माननीय न्यायालय सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एमपीध एमएलए जनपद बस्ती के स्थान पर विज्ञापन माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्ती स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया था। जिसको सुधार कराते हुए 16 नवंबर को स्थानीय समाचार पत्रों में पुनः धारा 82 की उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया। प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए क्षमा किया जाता है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 20 दिसंबर तय की गई है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में निबन्ध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट्स इन्डूरिंग दी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए किया गया। स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय के विद्यार्थियों ने निबन्ध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो. विनोद सिंह ने कहा की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकसित होता है। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है। विभाग का प्रयास समाज के लिए सुयोग्य नागरिक निर्माण करना है। प्रतियोगिता में सह कुलानुशासक प्रो मनोज शर्मा, एडिशनल डीएसडब्ल्यू प्रो अशोक कुमार कैथल, अर्थशास्त्र विभाग की डॉ अल्पना लाल, डॉ शशि लता सिंह, डॉ प्रीति सिंह, डॉ कामना सेन गुप्ता, डॉ उर्वशी सिरोही, डॉ दिनेश यादव एवं डॉ हरनाम सिंह उपस्थित रहे।

उजरियाँव कब्रिस्तान की बदहाली को दुरूस्त कराने की माँग

रविदास मेहरोत्रा से मिला सामाजिक संगठनो का प्रतिनिधीमण्डल

लखनऊ। राष्ट्रीय स्मजिक संगठनो का प्रतिनिधीमण्डल मो आफाक के नेतृत्व मे विधायक रविदास मेहरोत्रा से की मुलाकात कर दी ज्ञापन गँज शाहिदाँ कब्रिस्तान, उजरियाँव, गोमती नगर, लखनऊ जो कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह कब्रिस्तान लंबे समय से बदहाली का शिकार है। कब्रिस्तान की जमीन पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया हैं और जगह–जगह पर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल भी क्षतिग्रस्त है। कुछ पूर्व दागी वक्फ माफिया उसपर कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके उसपर मार्केट, फ्लैट, कमर्शियल कंपलेक्स और दुकान आदि बनाना चाहते हैं। इसकी खबरें कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में भी छप चुकी हैं। जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। कब्रिस्तान की रक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कब्रिस्तान के गेट भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं कब्रिस्तान में बिजली, सड़क व पानी आदि की व्यवस्था भी ठीक नहीं है जिस कारण लोगों को कब्रिस्तान में अपने प्रिय जनों के शव दफनाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। यह बातें राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कनवीनर मोहम्मद आफाक के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने गये सामाजिक संगठनो के एक प्रतिनिधीमण्डल ने कहीं। प्रतिनिधीमण्डल ने क्षेत्रीय

विधायक रविदास मेहरोत्रा से माँग की कि कब्रिस्तान की जमीन को वक्फ माफियाओं से बचाने के लिए और लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कब्रिस्तान में आवश्यक सड़क एवं बिजली पानी आदि की व्यवस्था करवाने के लिए अपनी विकास निधि से उपरोक्त आवश्यक कार्य करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें जिसके लिए क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी। प्रतिनिधीमण्डल में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कनवीनर मोहम्मद आफाक, शराब बन्दी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुर्तजा अली, तहफ्फुजे मसाजिद मदारिस दरगाह व कब्रिस्तान बचाओ समिति के अध्यक्ष हाजी फहीम सिददीकी, मोहम्मद अहमद सचिव, उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग, सैयद अली मुशीर जैदी, डॉ आफताब, इसार फाउण्डेशन के अध्यक्ष मौलाना इरशाद अहमद सिद्दीकी, फरीदा बहन , रोशन जहाँ बेन, शहजादे मंसूर अहमद, तुफैल अख्तर, परवेज अलम,मो मक्की अधिवक्ता हाइ कोर्ट, सहित विद्वान, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे

इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा जारी अलर्ट के बाद फार्मेसिस्ट फेडरेशन ने सभी फार्मेसिस्टो के लिए एडवाइजरी जारी की-सुनील यादव'

मेफिनेमिक एसिड से हो सकता है दुष्प्रभाव, सचेत रहें'

लखनऊ। मेफेनिमिक एसिड के दुष्परिणाम सामने आए हैं इसलिए इसके प्रयोग करते समय विशेष सावधानी एवं निगरानी रखने की आवश्यकता है इसके प्रयोग से इस्नोफीलिया, DRES ड्रग रिएक्शन विथ इस्नोफीलिया एंड सिस्टेमिक सिस्टम सिंड्रोम की संभावना है। इसमे चेहरे, लिंफ गांठ का बढ़ना, बुखार, अंतरिक अंगों में परेशानी, ब्लड में अनियमितता, चमड़े पर लाल धब्बे, चकत्ते, खुजली आदि शामिल हो सकते हैं। फार्मेसिस्ट फेडरेशन ने इस संबंध में फार्मा प्रोफेशनल,फार्मासिस्टों हेतु एक एडवाइजरी जारी की है। फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया डेटा के अनुसार भारतीय मेषजसंहिता आयोग ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, मरीजों और उपभोक्ताओं को इस संदिग्ध दवा के उपयोग से जुड़े दुष्परिणामों की संभावना की बारीकी से निगरानी करने की सलाह दी है। अलर्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी गई है कि मेफेनेमिक एसिड के दुष्परिणामों के प्रति सचेत रहें। यदि ऐसी प्रतिक्रिया सामने आती है, तो एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं रिपोर्टिंग फॉर्मध्दवाओं के साइड इफेक्ट रिपोर्टिंग फॉर्म (httu://www.luc.gov.in) भरकर एनसीसी–पीवीपीआई, आईपीसी को रिपोर्ट किया जा सकता है। एडीआर पीवीपीआई और पीवीपीआई का हेल्पलाइन नंबर 1800–180–3024 भी साझा किया गया है। मेफेनेमिक एसिड का प्रयोग संधिशोथ, ऑस्टियोआर्थराइटिस,माहवारी में दर्द, हल्के से मध्यम दर्द, सूजन, बुखार, दांत दर्द आदि में किया जाता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन अजय कुमार सिंह द्वारा डॉ विपिन यादव को उत्तर प्रदेश कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ का महासचिव नियुक्त किया गया है। डॉ विपिन यादव वर्तमान में जवाहर लाल नेहरू कॉलेज, महराजगंज में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉ विपिन यादव विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर कार्य भी किया है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षणआयोग के साथ 'राज्य स्तरीय बाल संवाद कार्यक्रम' सम्पन्न

लखनऊ। विज्ञान फाउंडेशन,लखनऊ विश्वविद्यालय, के एन एच जर्मनी, टी डी एच जर्मनी व डाइलॉग वर्क्स के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन 02 दिसम्बर 2023 को राधा कमल मुखर्जी हॉल, समाज कार्य विभाग में किया गया। कार्यक्रम मेंराज्य बाल अधिकार संरक्षणआयोग के माननीय सदस्यों के साथ प्रदेश के 23 जिलों के बच्चों का बाल हितग्राहियों के साथ संवाद कराया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी बातें राज्य बाल अधिकार संरक्षणआयोग की सम्मानितसदस्या डॉ शुचिता चतुर्वेदीव अनीता जी, आयोग के सम्मानित सदस्य श्री श्याम त्रिपाठी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रो – वी सी प्रोफेसर अरविन्द अवस्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित प्राक्टर डॉ राकेश द्विवेदी, सामाजिक कार्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आर के सिंह व अन्य संस्थाओं के सम्मानित अतिथियों के सामने रखीस कार्यक्रम में कई संस्थाओं के साथियों ने भी अपना वतक्तव्य रखा। इनमें वाटर ऐड से फर्रूख रहमान खान, एन एसी जी से वैभव, यू पी फोर्सेस से रामायण यादव, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग के सदस्यों ने भी प्रतिभाग किया। बच्चों ने संवाद में कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें प्रमुख थे स्कूल ना चलना, मंद बुद्धि बच्चे, मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल के बारे में, बच्चों की बंधुआ मजदूरी के बारे में ,बाल मजदूरी के बारे में, बस्तियों के विस्थापन, नदी से विस्थापन के बारे में, बच्चों के साथ हिंसा, पोषण के बारे में, क्षेत्र में सरकारी स्कूल का ना होने का नुकसान तथा स्कूल की अन्य दिक्कतों के बारे में बात की। इन सबकी बात सुनने के बाद, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सम्मानित सदस्यों सुश्री शुचिता जी व श्री श्याम त्रिपाठी जी ने सबकी बात सुन कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

कुलपति ने दीक्षांत समारोह स्थल का किया निरीक्षण

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने 6 दिसंबर को होने वाले 66वें दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले गेट संख्या 2 के पास निरीक्षण करके वहां पर लगने वाले बैनर, गेट के बारे में निर्देशित किया। तत्पश्चात कुलपति ने उस स्थल का भी निरीक्षण किया। जहां पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण व उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद कुलपति ने कला संकाय प्रांगण में तैयार हो रहे पंडाल का निरीक्षण किया। उपस्थित अधिकारियों को शोभा यात्रा के आने–जाने का मार्ग, साफ सफाई और सौंदर्य करण का विशेष रूप से ध्यान रखने का निर्देश दिया।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।